कोरोना के चलते माशिमं ने नवंबर में कम किया था 10वीं-12वीं का सिलेबस

एमपी बोर्ड का बेतुका निर्णय: परीक्षा से पहले सिलेबस में बढ़ाए चैप्टर, तनाव में स्टूडेंट्स

रामचन्द्र पाण्डेय ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

पीपुल्स समाचार
मुद्दा

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा से दो माह पहले बेतुका निर्णय लेते हुए फिर 10वीं और 12वीं के सिलेबस में बदलाव कर दिया है। मंडल ने इसी सत्र में नवंबर में कोरोना काल में प्रभावित हुई पढ़ाई को देखते हुए सिलेबस 30 प्रतिशत कम कर दिए थे। उस समय जो चैप्टर हटाए गए थे, उनमें से कुछ चैप्टर फिर से सिलेबस में शामिल कर प्रश्न-पत्र तैयार कराए जा रहे हैं। इससे स्टूडेंट्स की परेशानी बढ़ गई है।

स्टूडेंट्स और पैरेंट्स तनाव में हैं कि इतने कम समय में जोड़े गए विषय की तैयारी कैसे हो पाएगी। जानकारी के अनुसार, मंडल ने 12वीं में गणित, हिंदी, अंग्रेजी, कॉमर्स और बॉयोलॉजी में नए चैप्टर जोड़े हैं। गणित में दो, जनरल इंग्लिश में दो और स्पेशल इंग्लिश में 3 चैप्टर जोड़े गए हैं। इसी तरह 10वीं में भी कुछ चैप्टर जोड़े गए हैं। दरअसल, कोरोना काल में केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार, सीबीएसई सहित अन्य बोर्डों को सिलेबस 30 प्रतिशत कम करने के निर्देश दिए गए थे। सीबीएसई ने 30 प्रतिशत कोर्स कम करते हुए अलग-अलग चैप्टरों से कुछ टॉपिक कम किए थे। वहीं माशिमं के तत्कालीन चेयरमैन राधेश्याम जुलानिया ने चैप्टर ही हटवा दिए थे। उसी के अनुसार स्कूलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई भी कराई गई और उसी के अनुसार नया पैटर्न लाकर ब्ल्यू प्रिंट भी जारी किया गया था। जुलानिया के तबादले के बाद पीएस स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी के पास चेयरमैन का प्रभार है। उन्होंने फिर से सीबीएसई द्वारा कम किए गए कोर्स को मान्य कर ब्ल्यू प्रिंट जारी कराया है। इसके चलते प्रत्येक विषय में दो-दो चैप्टर बढ़ गए हैं। इस तरह हर विषय में लगभग 25 से 30 प्रतिशत कोर्स बढ़ गया है।

Badri Gautam

सीधी बात
उमेश सिंह, सचिव, माशिमं

- **परीक्षा के ऐन पहले नए चैप्टर बढ़ाना क्या सही है। इससे बच्चों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा?**
  - बच्चों के लिए कोर्स में जो बहुत जरूरी है, उसे ही शामिल किया गया है। सभी विषयों में चैप्टर नहीं बढ़ाए गए हैं। टीचर्स को भी अतिरिक्त जोड़े गए कोर्स से प्रश्न और अंकों का रेशियो कम करने को कहा गया है।
- **सिलेबस में बार-बार बदलाव क्यों किया जा रहा है, सीबीएसई ने एक बार में ही सिलेबस कम कर दिए थे?**
  - प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार, सीबीएसई के कोर्स में कटौती की गई थी, इसलिए उसके अनुसार प्रश्न पत्र तैयार कराए जा रहे हैं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए दोबारा बदलाव करने की जरूरत पड़ी है।
- **जो कोर्स बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, उसे जोड़ने से रिजल्ट खराब नहीं होगा?**
- कोर्स ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है। अभी परीक्षा में दो माह बचे हैं, बच्चों की तैयारी करा दी जाएगी। उनका रिजल्ट खराब नहीं होने दिया जाएगा।

12वीं के इन विषयों में बढ़े चैप्टर

- **गणित:** दो चैप्टर (वेक्टर मैथ एवं ट्रिग्नोमेट्री)
- **जनरल इंग्लिश:** दो चैप्टर बढ़ाए
- **स्पेशल इंग्लिश:** तीन चैप्टर बढ़ाए
- **हिन्दी:** दो चैप्टर बढ़ाए गए हैं

रिजल्ट पर पड़ेगा असर

नए ब्ल्यू प्रिंट के अनुसार जनरल इंग्लिश में दो चैप्टर और स्पेशल इंग्लिश में तीन चैप्टर बढ़ गए हैं। बच्चों को नए ब्ल्यू प्रिंट के अनुसार तैयारी कराई जा रही है। इससे रिजल्ट में थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा।
राजेश सिंह, अंग्रेजी टीचर

अभी हमारे पास शासन का कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया है। हां, जो नया ब्ल्यू प्रिंट आया है, उसमें जो सिलेबस पहले कम किया गया था, उसे जोड़ दिया गया है। शिक्षक उस कोर्स की तैयारी करा रहे हैं।
पुष्पलता राव, प्राचार्य, कमला नेहरू स्कूल, टीटी नगर

हमें मैथ्स के टीचर ने अभी बताया है कि वेक्टर गणित और ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी पड़ेगी। इसमें पांच एक्सरसाइज हैं। इसके लिए लगभग 30 फार्मूले हल करने होंगे। अब नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। डर लग रहा है कि कहीं नंबर कम न हो जाएं।
सुरेश कुमार, स्टूडेंट 12वीं, नवीन हायर सेकंडरी स्कूल, अरेरा कॉलोनी

सीबीएसई : 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बदलाव

एजेंसी ● नई दिल्ली

editor@peoplessamachar.co.in

सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के लिए कुछ विषयों की बोर्ड परीक्षा की नई तारीखें जारी की हैं। इनमें गणित, भूगोल और भौतिक विज्ञान शामिल हैं। दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और 10 जून को खत्म होंगी। पहले 12वीं की परीक्षा 14 जून को समाप्त होनी थी। सामान्य तौर पर लिखित परीक्षाएं फरवरी में शुरू होती थीं और मार्च में समाप्त होती थीं, लेकिन इस बार कोविड के चलते यह आगे बढ़ गईं।

Badri Gautam

12वीं का शेड्यूल

विषय	पुराना	नया
फिजिक्स	13 मई	08 जून
मैथ्स	01 जून	31 मई
ज्योग्राफी	02 जून	03 जून

इसके अलावा पहले 13 और 14 मई को भी कुछ विषयों की परीक्षाएं होनी थीं। अब इन दोनों तारीखों में कोई परीक्षा नहीं होगी।

10वीं का शेड्यूल

विषय	पुराना	नया
साइंस	15मई	21मई
मैथ्स	21मई	02जून

फ्रेंच, जर्मन, अरबी, संस्कृत, रशियन, ऊर्दू और पंजाबी की तारीखें भी बदली गई हैं।

सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा की तिथियों में किया बदलाव

नई दिल्ली, जेएनएन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड की कुछ विषयों की परीक्षा की तिथियों में बदलाव कर दिया है। बोर्ड ने बदली हुआ कार्यक्रम भी जारी किया है। नई डेट सीट के मुताबिक, 10वीं के विज्ञान विषय की परीक्षा अब 21 मई को होगी। इससे पहले यह परीक्षा 15 मई को होनी थी। गणित की परीक्षा 21 मई को होने वाली थी, जो अब दो जून को होगी। 12वीं के कुछ विषयों का भी परीक्षा कार्यक्रम बदला गया है। इस कक्षा की फिजिक्स की परीक्षा 13 मई को होने वाली थी, जो अब 8 जून को होगी। यही नहीं, 12वीं कक्षा के विज्ञान और वाणिज्य के लिए गणित की जो प्रायोगिक परीक्षा पहले एक जून को होनी थी, वह अब 31 मई को होगी। बोर्ड ने कला संकाय के लिए भूगोल की परीक्षा दो जून की जगह तीन जून को कराने का फैसला किया है। संशोधित डेट सीट के मुताबिक, अरबी और संस्कृत भाषा के पेपर गुरुवार, 3 जून को और मलयालम, पंजाबी, रूसी, उर्दू कोर्स-बी के पेपर अब शनिवार, 5 जून को होंगे। नए शेड्यूल के अनुसार 13 मई से 16 मई के बीच कोई पेपर नहीं होगा। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चार मई से शुरू होंगी और दस जून को समाप्त होंगी। सामान्य तौर पर व्यावहारिक परीक्षाएं जनवरी में होती थीं, जबकि लिखित परीक्षाएं फरवरी में शुरू हो जाती थीं। ये परीक्षाएं मार्च में समाप्त हो जाती थीं। इस बार कोरोना के कारण ये परीक्षाएं देर से आयोजित की जा रही हैं।

10वीं की विज्ञान की परीक्षा अब 21 मई को होगी

Badri Gautam

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कोरोना समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

भोपाल और इंदौर में 8 मार्च से रात्रि कर्फ्यू

अगर मामलों में कमी नहीं आई तो लगेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू

स्टार समाचार | भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल और इंदौर में कोरोना के प्रकरणों में लगातार वृद्धि हो रही है। मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती जरूरी है। यदि अगले 3 दिन में कोरोना के प्रकरणों में गिरावट नहीं हुई तो 8 मार्च से भोपाल और इंदौर में रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह निर्देश मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा बैठक में दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इंदौर में लंदन वैरिएंट से प्रभावित 6 मरीज मिले हैं। लंदन वैरिएंट का संक्रमण अधिक घातक है। इसकी संक्रामक क्षमता तुलनात्मक रूप से अधिक है। इंदौर में पिछले सप्ताह प्रतिदिन औसतन 151 प्रकरण बढ़े हैं। इसी प्रकार भोपाल में 78, जबलपुर में 16, बैतूल में 13 और छिंदवाड़ा व उज्जैन में 11-11 प्रकरणों की प्रतिदिन औसतन वृद्धि हुई है। इंदौर में पिछले 15 दिनों में प्रकरणों की संख्या दोगुनी हो गई है। इस गंभीरता को देखते हुए इंदौर और भोपाल में सावधानियां बरतना और सख्ती करना आवश्यक है।

Badri Gautam

एक दिन में 14 लाख लोगों को लगा टीका

नई दिल्ली। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को कोरोना के दैनिक मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में देश में 16,838 नए मामले सामने आए हैं, अब देश में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1.1 करोड़ के पार चला गया है। वैक्सीनेशन में प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने के बाद पहली बार भारत में एक दिन में करीब 14 लाख डोज दिए गए हैं। कल के मुकाबले यह 40% ज्यादा है। पिछले चार दिनों में दिए गए डोज की संख्या दोगुने से ज्यादा हो गई है। 1 मार्च को 5.52 लाख डोज दिए गए थे, जो 4 मार्च को बढ़कर 13.88 लाख डोज हो गए।

स्कूल और कॉलेजों में मॉस्क अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शासकीय तथा गैर-शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में मास्क का उपयोग अनिवार्य किया जाए।

महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए टेस्ट रिपोर्ट लाना अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, उज्जैन और महाराष्ट्र से लगे जिलों में कोरोना से प्रभावित प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में हालत में स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाए। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। इसकी जवाबदारी बस ऑपरेटरों की होगी। बस ऑपरेटर रिपोर्ट के आधार पर ही यात्रियों को बस में प्रवेश दें। राज्य की सीमा पर पुख्ता चैकिंग की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि महाराष्ट्र सीमा से लगे जिलों पर निगरानी रखी जाए।

इंदौर में तीन दिन रखी जाएगी विशेष नजर

इंदौर कमिश्नर ने कहा नया संक्रमण तेजी से फैल सकता है, इसीलिए रोको-टोको अभियान को ज्यादा तेजी और ताकत से लागू करना होगा। सीएम ने भी इसे सख्ती से रोकने के निर्देश दिए हैं। शहर में 3 दिन तक हालात पर नजर रखी जाएगी, संक्रमण कम नहीं होने पर नाइट कर्फ्यू पर विचार किया जाएगा। 'संक्रमितों में राजेंद्र नगर का एक, तेजाजी नगर इलाके के तीन, पलासिया इलाके का एक और प्रेम नगर इलाके का एक पेशेंट शामिल हैं। नया स्ट्रेन 10 से 40 साल की उम्र के मरीजों में मिला है। सभी मरीज पुरुष हैं होम आइसोलेशन में हैं। इसमें से किसी भी मरीज की विदेश आने-जाने की हिस्ट्री नहीं है।

कोरोना के नए मामले में आई मामूली गिरावट

नई दिल्ली। पिछले 24 घंटे में देश में 16,838 नए मामले सामने आए हैं, अब देश में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1.11 करोड़ के पार चला गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में देश में 16,838 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों का आंकड़ा बढ़कर 1,11,73,761 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 113 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे अपना दम तोड़ा है और कोविड-19 की वजह मृतकों की संख्या 1,57,548 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 13,819 मरीज ही कोरोना से ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं।

शिक्षा सुधार के लिए बनेगी टास्क फोर्स, मुख्यमंत्री ने कहा-

शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान, कौशल और नागरिक के संस्कार देना

स्टार समाचार | भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना होना चाहिए। नई शिक्षा नीति में इन तीनों बातों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। इन्हें मध्यप्रदेश में लागू किया जाएगा। कक्षा छठवीं से व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शिक्षा का अर्थ तोते की तरह रटना, बस्ते के बोझ से दबे रहना तथा परीक्षा देना नहीं है। शिक्षा से बच्चों की प्रतिभाओं का प्रकटीकरण होना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों के शिक्षण-प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा 'शिक्षक-शिक्षा का कायाकल्प' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया।

Badri Gautam

समाज के सहयोग से शिक्षा

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शिक्षा देना केवल सरकार का कार्य नहीं है। समाज के सहयोग से शिक्षा दी जानी चाहिए। इस क्षेत्र में विद्या भारती जैसी संस्थाएं काफी अच्छा कार्य कर रही हैं।

मनमर्जी नहीं चलेगी

मुख्यमंत्री चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षण संस्थाएं अमर्यादित शिक्षा देकर विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करें, यह नहीं चलेगा। यदि कोई संस्थान गलत शिक्षा देता है, तो उसे रोका जाएगा। हम आतंकवादी नहीं बनने दे सकते। स्कूलों के नाम पर कुछ भी खोला जाए, यह नहीं चलेगा।

शिक्षक रतन चंद जैन को याद किया

मुख्यमंत्री ने अपने गांव जैत के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रतन चंद जैन को याद करते हुए कहा कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा मेरे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थियों को रामचरित मानस पढ़ाया करते थे। 'इससे न केवल मैं वक्ता बना, मुझे श्री राम की मर्यादाओं के अनुरूप जीवन जीने की प्रेरणा मिली'।

आत्म-निर्भर के रोड मैप में शिक्षा अहम

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए बनाए गए रोड मैप में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त सीएम राइज स्कूल खोले जाने के लिए डेढ़ हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अच्छी तकनीकी शिक्षा के लिए ग्लोबल स्किल पार्क तथा आदर्श आईटीआई बनाए जा रहे हैं।

मंथन से उपजा विचार रूपी अमृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सार्थक होगा : परमार

स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग सतत प्रयास कर रहा है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था भारत केंद्रित, गुणवत्तापूर्ण और ज्ञान आधारित होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान और एनसीटीई के संयुक्त तत्वधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिक्षक-शिक्षा के ऊपर व्यापक मंथन और चिंतन किया जाएगा। इस मंथन से उपजा विचार रूपी अमृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मील का पत्थर साबित होगा। संगोष्ठी के दौरान प्राप्त सिफारिशों को मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

स्कूल खुल गए, लेकिन डर ऐसा कि आनलाइन ही कर रहे पढ़ाई

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। बोर्ड परीक्षा को लेकर स्कूलों में कक्षाएं तो लग रही हैं, लेकिन विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम बनी हुई है। ज्यादातर विद्यार्थी सुरक्षित तरीके से घर में रहकर ही पढ़ाई करने पर जोर दे रहे हैं। वे आनलाइन कक्षाओं का ही लाभ उठा रहे हैं। शुरू में जहां 10 फीसद ही विद्यार्थी स्कूल पहुंच रहे थे। अब उनकी मौजूदगी 70 फीसद तक हो गई है, लेकिन 30 फीसद अभी तक घर में आनलाइन के सहारे कोर्स पूरा करने में जुटे है। छात्र कोरोना संक्रमण और सुरक्षा कारणों के चलते स्कूलों से दूरी बनाए हुए हैं। स्कूल आने के लिए अभिभावकों की सहमति भी लेनी जरूरी है ऐसे में शिक्षक भी परेशान हैं। इन दिनों शहर के अधिकांश स्कूलों में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है।

एक से पांच तक स्कूल नहीं खुलेंगे: शासन ने भी साफ कर दिया है कि कक्षा एक से पांचवी तक स्कूल नहीं खुलेंगे। यहां आनलाइन ही पढ़ाई होगी। ऐसे में स्कूल पहले ही आनलाइन पढ़ाई पूरी करवा चुके हैं। अब ऐसे स्कूल आनलाइन ही परीक्षा लेने की तैयारी में जुट गए हैं। ज्यादातर स्कूलों ने पांचवीं तक के विद्यार्थियों की परीक्षाओं का कार्यक्रम तक जारी कर दिया है। मार्च तक अधिकांश स्कूलों में परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या सामने आ रही है तो वहीं बच्चों के पास मोबाइल न होना भी परेशानी की वजह बन रहा है। जिले के 2250 से अधिक प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं।

दोहरी पढ़ाई को मजबूर शिक्षक

छात्रों की आधी मौजूदगी के कारण कक्षाओं में शिक्षकों को दोहरी पढ़ाई करवानी पड़ रही है। पहले आफलाइन क्लास होती थीं है अब आफलाइन के अलावा आनलाइन भी कक्षाएं लेनी पड़ रही हैं। दोहरी जवाबदारी से शिक्षक परेशान हैं। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं ऐसे में उनके सामने परिणाम सुधारने की भी चुनौती बनी है।

कोविड-19 को देखते हुए फिलहाल प्राइमरी और मिडिल में कक्षाएं आनलाइन ही लगाई जा रही हैं। ऑनलाइन माध्यम से उन्हें पढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

-डॉ. आरपी चतुर्वेदी, डीपीसी

Badri Gautam

स्कूलों में फीस प्रतिपूर्ति में अनियमितता जांच में खुली पोल, जिला प्रोग्रामर दोषी

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले के निजी स्कूलों को आरटीई के तहत फीस प्रतिपूर्ति के रूप में अनियमित भुगतान हुए। इस आरोप की जांच के लिए बनी कमेटी ने भी माना कि नियमविरुद्ध तरीके से राशि का भुगतान किया गया। अशासकीय विद्यालयों की जांच का प्रस्ताव आर्थिक अनियमितता किए जाने के आरोप सिद्ध होने के बाद 640 अशासकीय विद्यालयों की गहन जांच के लिए विभाग को लिखा गया है।

जांच कमेटी ने जिला समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान और जिला प्रोग्रामर पारुल राय को इसमें दोषी माना है। जांच कमेटी ने जांच में पाया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों को जारी फीस प्रतिपूर्ति में वित्तीय अनियमितता बरती गई है। इससे शासन को भी अर्थिक क्षति का नुकसान हुआ है। इसमें 67 लाख 10 हजार की वसूली के लिए एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

जांच के दौरान पाया गया जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों ने वेदांत पब्लिक स्कूल भेड़ाघाट को 53 लाख 9 हजार 640 रुपए फीस प्रतिपूर्ति में फर्जी तौर पर बच्चों के नाम दर्ज कर वित्तीय अनियमितता की गई है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामर भी शामिल है। उक्त आशय के आरोपों को प्रारंभिक जांच में सही माना गया है।

जिपं सदस्य ने लगाए थे आरोप: जिला पंचायत सदस्य विजय क्रांति पटेल एवं उन्नति मेश्राम द्वारा जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर निजी स्कूलों को फर्जी तरीके से फीस प्रतिपूर्ति की राशि आवंटित किए जाने की शिकायत मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग एवं तत्कालीन कैबिनेट मंत्री प्रियव्रत सिंह से की गई थी।

Badri Gautam

काम किया नहीं, वेतन लिया

जांच प्रतिवेदन में कहा गया है कि अधिकृत कर्मचारियों का वेतन आहरित न करते हुए अनाधिकृत कर्मचारियों का वेतन आहरित किया गया है। यहां तक कि कई कर्मचारियों को बिना काम के वेतन दिया गया।

सेवा पुस्तिका अनुमोदन न कराने वाले प्राचार्यों पर हो कार्रवाई

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। अध्यापकों की सेवा पुस्तिका में अनुमोदन नहीं करने वाले प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यापक प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक मुकेश सिंह ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं की अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों कि सेवा पुस्तिकाओं का अनुमोदन सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन प्राप्त करने वाले अध्यापक संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में सम्मिलित प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक की सेवा पुस्तिकाओं का अनुमोदन कोष एवं लेखा से कराया जाना है। इसके बावजूद जिले के प्राचार्यों की उदासीनता के कारण अध्यापक संवर्ग की सेवा पुस्तिका का अनुमोदन कोष एवं लेखा को ऑनलाइन रिक्वेस्ट नहीं भेजी जा रही है। जिससे कोष एवं लेखा के अधिकारियों द्वारा संबंधित सेवा पुस्तिका का अनुमोदन नहीं हो पा रहा है, जिससे अध्यापकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा द्वारा स्पष्ट आदेश कर सभी प्राचार्यों एवं आहरण संवितरण अधिकारियों से जल्द सेवा पुस्तिका के अनुमोदन का पत्र भी जारी कर चुके हैं उसके बाद भी समस्या का निदान नहीं हो रहा है।

संघ के मुकेश सिंह, आलोक अग्निहोत्री, प्रणव साहू, नितिन अग्रवाल, तरुण पंचोली, राकेश दुबे, मनीष लोहिया, विष्णु पांडे, आनंद रैकवार, श्याम नारायण तिवारी, मनोज सेन, मो. तारीक, धीरेंद्र सोनी, गणेश उपाध्याय, विनय नामदेव, प्रियांशु शुक्ला, राकेश पांडे, विजय कोष्टी, मनीष शुक्ला, सुदेश पांडे, संतोष तिवारी, सतीश पटेल आदि ने कलेक्टर जबलपुर से मांग की है कि सेवा पुस्तिकाओं का अनुमोदन ना कराने वाले प्राचार्यों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

Badri Gautam

भास्कर पड़ताल जिले के 2669 प्राथमिक विद्यालयों के 1 लाख 5308 बच्चे प्रभावित

एमडीएम • स्कूली बच्चों के मिल्क पाउडर में कटौती कर सरकार ने बचाए 7 करोड़

भास्कर न्यूज | सतना

कोरोना की वैश्विक महामारी का साइड इफेक्ट जिले की प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के मध्यान्ह भोजन पर भी पड़ा है। कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई बंद कर दी गई थी। इसके साथ ही प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को फरवरी के उत्तरार्द्ध से लेकर अब तक उनके घरों तक पहुंचाकर मध्यान्ह भोजन योजना के तहत सूखा चावल पहुंचाकर प्रदाय करवाया जा रहा है लेकिन 11 माह से एमडीएम के तहत प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को मिल्क पाउडर नहीं दिया जा रहा है।

अभी भी शुरुआत की उम्मीद नहीं

जानकार सूत्रों की मानें तो जिले की उक्त स्कूलों के बच्चों को मिल्क पाउडर की आपूर्ति एमडीएम के तहत नहीं किए जाने से सरकार को करीब 7 करोड़ 29 लाख रुपए की बचत तो हुई, लेकिन सरकार के लिए बचत का यह फंडा जिले की प्राथमिक स्कूलों के करीब 1 लाख 5 हजार बच्चों के साथ किसी नाइंसाफी से कम नहीं है। इन्हीं सूत्रों के अनुसार विगत 11 माह से स्कूलें बंद होने से मिल्क पाउडर की योजना मौजूदा शैक्षणिक सत्र के दौरान शुरू होने की कोई उम्मीद फिलहाल नहीं है।

11 माह से नहीं हो रही आपूर्ति

इन्हीं सूत्रों के मुताबिक मार्च 2020 से लेकर जनवरी 2021 में अब तक शासकीय प्राथमिक स्कूलों को मिल्क पाउडर की आपूर्ति नहीं की गई है। हालांकि मई और जून के महीनों में अवकाश के कारण स्कूल बंद रहने पर दोपहर का भोजन और मिल्क पाउडर भी बंद कर दिया जाता था। अलबत्ता इसके बाद भी 11 माह के शैक्षणिक दिवसों से जिले के प्राथमिक स्कूलों के सभी बच्चे मिल्क पाउडर से वंचित तो हैं ही?

पहले 270 क्विंटल मिल्क पाउडर की हर माह होती थी खपत

पहले 270 क्विंटल मिल्क पाउडर की होती थी आपूर्ति शिक्षा विभाग के जानकारों के मुताबिक पिछले साल फरवरी तक हर महीने जिले में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत करीब 270 क्विंटल मिल्क पाउडर की आपूर्ति शासन द्वारा सुनिश्चित की जाती थी। इस मिल्क पाउडर की कीमत प्रति किलो करीब 300 रुपए होती थी। इस तरह 9 महीने से मिल्क पाउडर की सप्लाई न होने से शासन को करीब 7 करोड़ 29 लाख रुपए की बचत हुई।

फैक्ट फाइल

» जिले में शा. प्राथमिक स्कूल	2669
» दर्ज बच्चों की संख्या	1 लाख 5308
» कब से बंद है मिल्क पाउडर की आपूर्ति	मार्च 2020 से
» पहले हर महीने मिल्क पाउडर का वितरण	270 क्विंटल
» प्रति किलो कीमत	3 सौ रुपए
» कुल आंगनबाड़ी केन्द्र	3 हजार 34
» कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे	2 हजार

आंगनबाड़ी केन्द्रों में जारी

उधर महिला बाल विकास के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आंगनबाड़ी केन्द्रों में मिल्क पाउडर की आपूर्ति कोविड-19 के बावजूद भी यथावत की जा रही है। बताया जाता है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में 0 से 5 साल तक के कुपोषित और अतिकुपोषित बच्चों को मिल्क पाउडर का घोल तैयार कर निर्धारित मात्रा में सप्ताह के दो दिन निरंतर दिया जा रहा है। जिले की आंगनबाडियों में ऐसे गरीब बच्चों की तादाद करीब 20 से 22 हजार बताई जा रही है, जिन्हें मिल्क पाउडर का घोल बनाकर केन्द्रों में दिया जाता है।

कोविड-19 की वजह से कक्षाएं बंद होने के बावजूद सरकार द्वारा सूखा राशन, पहले की तरह और अब जनवरी से साथ में दाल, तेल और चिक्की का वितरण बच्चों को करवाया जा रहा है। हम मुख्यमंत्री से मिलकर आग्रह करेंगे कि प्राथमिक शालाओं के बच्चों को पहले की तरह मिल्क पाउडर की आपूर्ति जल्द से जल्द शुरू करवाए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करवाई जाए।

शैलेन्द्र त्रिपाठी, अध्यक्ष राज्य शिक्षक संघ

Badri Gautam

तो चली जाएगी तकनीकी महाविद्यालयों की मान्यता!

मध्य स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

बीते एक दशक में मप्र में कुकरमुत्तों की तरह खुले तकनीकी महाविद्यालयों (इंजीनियरिंग कॉलेजों) ने शिक्षा की गुणवत्ता को बिगाड़ कर रख दिया है। इसकी वजह से अब प्रदेश के निजी तकनीकी महाविद्यालयों (इंजीनियरिंग कॉलेजों) से निकलने वाले छात्रों को रोजगार तक हासिल करने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस स्थिति को देखते हुए अब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। इसके लिए अब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने तय किया है कि इस वर्ष उन तकनीकी महाविद्यालयों(इंजीनियरिंग कॉलेजों) को न तो मान्यता दी जाएगी और न ही निरंतरता का अप्रूवल दिया जाएगा, जिनमें बीते पांच सालों पहले और तृतीय सेमेस्टर में 30 प्रतिशत से कम प्रवेश हुए हैं। इसके साथ ही नए सत्र के लिए मान्यता और निरंतरता की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इसके लिए तकनीकी महाविद्यालयों(इंजीनियरिंग कॉलेजों) से 31 अप्रैल तक आवेदन बुलाए गए हैं। इस बार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा कॉलेजों के निरीक्षण का काम ऑनलाइन किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में तकनीकी महाविद्यालयों(इंजीनियरिंग कॉलेजों) में बहुत कम प्रवेश वाले कॉलेजों पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा कार्रवाई शुरू करने पर उनके संचालकों द्वारा तर्क दिया गया था कि भले ही पहले सेमेस्टर में 30 फीसद से कम प्रवेश हुए हों, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश की संख्या में तेजी से वृद्धि हो जाती है। इसलिए इस बार पहले के साथ थर्ड सेमेस्टर के प्रवेश देखे जाएंगे।

दयनीय है तकनीकी महाविद्यालयों की हालत

प्रदेश में संचालित 151 तकनीकी महाविद्यालयों (इंजीनियरिंग कॉलेजों) में से आधा सैकड़ा तकनीकी महाविद्यालय तो ऐसे हैं, जिनमें एक भी प्रवेश ही नहीं हुआ है। इनमें से भोपाल के 16 और इंदौर के 7 तकनीकी महाविद्यालयों शामिल हैं। इसी तरह से प्रदेश के 26 तकनीकी महाविद्यालय ऐसे हैं, जिनमें 30 प्रतिशत से कम प्रवेश हुए हैं।

Badri Gautam

10वीं-12वीं की परीक्षाओं के दौरान नहीं होंगे नगरीय निकाय चुनाव

भोपाल निप्र। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के दौरान चुनाव नहीं कराए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी पूरी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ईव्हीएम की चैंकिंग और सेटअप के लिए इंजीनियर मिलने में देरी हो रही है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 अप्रैल से 18 मई तक होंगी। इस हिसाब से देखें, तो चुनाव अप्रैल माह में होंगे या फिर मई के तीसरे सप्ताह में कराए जाएंगे, लेकिन ईव्हीएम के परीक्षण और सेटअप के लिए इंजीनियर कब आएंगे, यह अभी तक आयोग को जानकारी नहीं है। आयुक्त ने बताया कि ईव्हीएम देने वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इंजीनयर पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, तामिलनाडु, केरल, असम और पुद्दुचेरी भेज दिए हैं, जबकि मप्र में ईव्हीएम की चैकिंग के लिए 424 इंजीनियर्स की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम लगातार कंपनी के संपर्क में हैं, ताकि ईव्हीएम मशीनों की जांच जल्दी हो जाए।

आयुक्त सिंह ने इस संभावना से इंकार किया है कि कोरोना के मामले प्रदेश में बढ़ने के कारण चुनाव कुछ समय के लिए टाले जाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया, कोरोना संक्रमण के चलते इस बार वोटिंग का समय 1 घंटे बढ़ाया जा रहा है।

Badri Gautam

मॉडल स्कूल में ओजस यूथ क्लब की कार्यशाला आयोजित

पीपुल्स संवाददाता ● दमोह

मो.नं. 8435502322

ओजस यूथ क्लब शासकीय मॉडल विद्यालय में जिला बाल अधिकार मंच के सहयोग से 'स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यार्थी' विषय बौद्धिक गतिविधियों के तहत नाट्य कार्यशाला आयोजित हुई। पहले दिन दमोह के प्रतिष्ठित वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ मंच के वरिष्ठ सदस्य डॉ. संजय त्रिवेदी का व्याख्यान आयोजित किया गया। अपने उद्बोधन में उन्होंने बच्चों के लिए दैनिक दिनचर्या व आहारचर्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इसलिए सबसे पहले आपको स्वच्छ रहकर विद्यालय को भी स्वच्छता बनाए रखना है।

Badri Gautam

राष्ट्रीय युवा कोर्प के लिए आवेदन 20 तक आमंत्रित

भोपाल(आरएनएन)। खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय युवा कोर्प योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नेहरू युवा केन्द्र की गतिविधियों के संचालन एवं भारत सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार व सफल क्रियान्वयन के लिए एनवायव्ही स्वयं सेवकों का जिले के समस्त विकासखण्डों में एक वर्ष की कार्य अवधि के लिये नियुक्त किया जाना है।

ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रोफार्मा आदि विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाईन एवं ऑफलाईन आवेदन 20 मार्च 2021 तक जमा किये जा सकते हैं। जिला युवा समन्वयक के अनुसार आवेदनकर्ता की आयु 01 अप्रैल 2021 को 18 वर्ष से 29 वर्ष व शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं पास होना चाहिये। चयनित आवेदनकर्ता को जिस विकासखण्ड से आवेदन कर रहा है वहां का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र नहीं होना चाहिये। चयनित आवेदनकर्ता को 5 हजार प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा।

Badri Gautam

जहां स्वाध्यायी छात्र बैठेंगे वहां पर पिछले वर्ष की तरह लगाया जाएगा अतिरिक्त बल

लगाया जायेगा अतिरिक्त पुलिस बल, हर दिन होगा निरीक्षण

भोपाल(आरएनएन)। अगले मई माह से प्रारंभ हो रही दसवीं बारहवी की परीक्षाओं को लेकर बोर्ड ने हर केन्द्र पर नजर रखने का प्लान तैयार किया है। जिन परीक्षा केन्द्रों पर स्वाध्यायी छात्र बैठ रहे हैं। उन्हें पिछले वर्ष की तरह इस बार भी संवेदनशील की श्रेणी में रखने पर विचार चल रहा है। यहां पर अतिरिक्त पुलिस बल निगरानी के लिए रखा जाएगा। कारण है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान बोर्ड को ऐसे केन्द्रों पर वाद-विवाद की घटनाएं देखने को मिलीं हैं।

अधिकारियों का कहना है कि जिन सेंटरों पर स्वाध्यायी छात्र बैठेंगें। वहां पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सभी हालातों का जायजा लेने के बाद मंडल के निर्देश पर इन सभी केन्द्रों को पूर्व की तरह संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। यहां पर अन्य सामान्य केन्द्रों की अपेक्षा ज्यादा पुलिस बल लगाया जाएगा। ऐसी रणनीति बनाई गई है कि इन हर केन्द्रों पर प्रतिदिन उड़नदस्ता परीक्षाओं की जांच करने के लिए पहुंचेगा। शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मंडल की जो गाइड लाइन है। उसी के अनुसार विधिवत नियमों का पालन कराते हुए परीक्षाएं प्रारंभ करवाई जाएं। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षाओं के लिए हमारी समस्त तैयारियां पूर्ण हैं, लेकिन बच्चों को कोरोना से सुरक्षित रखना भी हमारे लिये बड़ी चुनौती है। भारत सरकार की पूरी गाइडलाइन का केन्द्रों पर पालन करवाया जाएगा।

शुद्ध पेयजल के निर्देश: मंडल ने जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि परीक्षा केन्द्रों पर शुद्ध पेयजल बच्चों को उपलब्ध कराया जाये। स्कूलों में पानी की टंकियों का परीक्षण करवाया जाये। यदि गंदगी हो तो तत्काल इनकी सफाई हो। ताकि कोरोना का प्रकोप न पनप पाये। परीक्षाओं के दौरान गर्मी पड़ने की संभावना है। इस कारण अभी से निर्देशित किया गया है कि गर्मी के वक्त परीक्षार्थियों के लिए ठंडे पाने की व्यवस्था की जाए। ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने कहा है कि जिन केन्द्रों का अनुमोदन कर मंडल को भेजा गया था। वहां से अनुमोदित सूची आते ही यह तय हो जाएगा कि कितने केन्द्रों पर बोर्ड परीक्षा करवाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि मंडल के जो नियम हैं, उसी के अनुसार ही परीक्षाएं संपादित करवाई जाएंगी।

कड़ी सुरक्षा निगरानी में पूर्व की तरह जिलों में भेजी जाएगी परीक्षा सामग्री

भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा अपनी पुरानी पद्धति के अनुसार जिलों में परीक्षा सामग्री भेजने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि नियम के अनुसार यह सामग्री भेजी जाएगी। संभवना है कि पूरे मार्च माह तक यह काम चलेगा। बताना होगा कि बोर्ड के तत्कालीन चेयरमेन राधेश्याम जुलानिया ने परीक्षा पद्धति में कई बदलाव किए थे। कुछ दिन पूर्व उनके सभी निर्णय को शासन ने बदल दिया था। दो दिन पूर्व ही जुलानिया की जगह राज्य शासन ने शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरूण शमी को बोर्ड चेयरमेन का अतिरिक्त प्रभार दिया है। अब उन्हीं के निर्देशन में परीक्षा संबंधी पूरा कार्य हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अप्रैल अंत से प्रारंभ हो रही परीक्षाओं की पूरी तैयारियां हैं। पूर्व की तरह नियम के अनुसार पहले उन उत्तर पुस्तिकाओं की जांच होगी, जिन प्रश्न पत्रों की परीक्षा संपन्न हुई होगी । इसके बाद टाइम टेबल के अनुसार क्रमवार कापियों के मूल्यांकन का काम चलेगा। मंडल का कहना है कि अभी भी कोरोना वायरस की दहशत से सावधान रहने की जरूरत है। इस कारण सभी जिलों में कलेक्टरों एवं सक्षम अधिकारियों से कहा गया है कि वह भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार परीक्षाएं कराने की तैयारी करे। बच्चों की सुरक्षा के साथ-साथ शिक्षकों को भी परीक्षा समय में सावधानी बरतने का आग्रह करें। क्योंकि काम की व्यस्तता के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्याना देना भी उतना ही जरूरी है। बोर्ड में अधिकारियों का कहना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए परीक्षाओं में पूरे इंतजाम होंगे। यदि इसका संक्रमण हुआ तो निश्चित रूप से दिक्कत उठानी पड़ेगी। इस कारण पहले से ही सतर्क किया गया है। इधर बोर्ड की चेयरमेन ने यहां का प्रभार संभालते ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी नियम प्रक्रिया के साथ काम हो। जिला शिक्षा अधिकारियों ने परीक्षा केन्द्रों की जो सूची भेजी है। उसके अनुसार अपने स्तर पर भी केन्द्रों का अवलोकन करवाया जाए। ताकि निष्पक्ष परीक्षाएं संपादित करवाई जा सकें।

Badri Gautam

एक दिन की SDM बनकर बोली सोना-अब खूब करूंगी पढ़ाई

9वीं कक्षा में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी सोना का बढ़ा मनोबल, अब सीखेगी सिलाई-कढ़ाई, अगले सत्र में स्कूल में भी दाखिला लेगी

विनय शुक्ला ● शहडोल
मो.नं. 9407813266

पीपुल्स समाचार स्पेशल

एसडीएम की कुर्सी पर बैठी सोना, साथ में एसडीएम प्रियांशी भंवर और सोना की मां।

ब्यौहारी तहसील की एसडीएम प्रियांशी भंवर ने ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को सबल और उन्हें शिक्षित करने के लिए अपनी पहल 'मिशन तेजस्विनी' के तहत गुरुवार को एक 18 साल की बालिका को एक दिन के लिए एसडीएम बनाया।

उनकी इस पहल से बच्ची का मनोबल बढ़ा और सोना चर्मकार नाम की इस बेटी अब आगे खूब पढ़ाई करने का मन बना लिया है। सोना का कहना है कि 9वीं फेल होने के बाद पढ़ाई की इच्छा छूट चुकी थी। मैडम ने मनोबल बढ़ाया है इसलिए अब आगे खूब पढ़ाई करूंगी। मेरा प्रयास रहेगा की अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोई उच्च पद प्राप्त करूं। सोना ने बताया कि एक दिन की एसडीएम बनने के बाद एसडीएम का काम करीब से देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। कई जगह जाकर कामों का निरीक्षण भी किया।

मजदूरी करते हैं माता-पिता

जानकारी के अनुसार, सोना पिता मंगल प्रसाद चर्मकार(18), ब्यौहारी के ग्राम झरोसी की रहने वाली है। वह 27 फरवरी ब्यौहारी एसडीएम प्रियांशी भंवर से मिली थी। बातचीत में एसडीएम को पता चला कि वह तीन वर्ष पूर्व, 9वीं में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी है। सोना ने यह भी बताया कि, उसके माता-पिता मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। परिवार की स्थिति को देखते हुए एसडीएम ने बच्ची को उसकी मां के साथ दोबारा 1 मार्च को बुलवाया और समझाइश दी। इसके बाद गुरुवार को एक दिन का एसडीएम बनाया।

प्रशासनिक कार्यों को जाना, SDM के साथ खाना खाया

एसडीएम प्रियांशी भंवर ने बताया कि सोना को कार्यालय की प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी दी गई। इसके बाद सोना को अपने निवास पर ले जाकर दोपहर का भोजन करवाया और नगर परिषद ब्यौहारी के मतदान केन्द्रों का भ्रमण कराया। एसडीएम द्वारा एनआरएलएम को निर्देशित किया कि, अगले माह में बालिका को वोकेशनल एजुकेशन के तहत सिलाई, कढ़ाई का प्रशिक्षण दें एवं अगले शैक्षणिक वर्ष में उसे पुनः स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए बीईओ को निर्देशित किया है।

फेसबुक पर संपर्क कर सकती हैं बच्चियां: प्रियांशी

एसडीएम प्रियांशी भंवर ने 'पीपुल्स समाचार' से हुई बातचीत में बताया कि, तेजस्विनी नामक इस कार्यक्रम की शुरूआत मैंने छत्तरपुर में किया था। इसके बाद यहां पर ट्रांसफर होकर आई, तो यहां भी इसकी शुरूआत की है। जिसका उद्देश्य बच्चियों में आत्मविश्वास को जगाकर उन्हें सबल और शिक्षित बनाना है। पहले हम 10वीं व 12वीं की टॉपर लड़कियों को चयनित करते थे, लेकिन अब चयन में थोड़ा परिवर्तन किया गया है।

Badri Gautam

आयुक्त ने मांगी 9वीं और 11वीं के छात्रों की सत्यापित जानकारी

निर्देश • लोक शिक्षण संचालनालय तैयार कराएगा प्रश्न पत्र

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षा महकमे अधिकारियों से जानकारी लेते आयुक्त।

भास्कर न्यूज | सतना

लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त द्वारा शुक्रवार को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में जिला शिक्षा अधिकारी सहित समस्त प्राचार्यों को 9वीं और 11वीं की सही छात्र संख्या सत्यापन कर लोक शिक्षण संचालनालय भेजने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि इसी छात्र संख्या के मान से ही वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। आगामी कुछ दिनों में ही 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा की तिथियां भी घोषित कर दी जाएंगी। आयुक्त ने समस्त प्राचार्यों से कहा है कि परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर ही आयोजित होगी, जिसके लिए अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दें। इसके अलावा एक्सीलेंस एवं मॉडल स्कूलों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। आयुक्त द्वारा बनाए गए परीक्षा केन्द्रों की जानकारी भी प्राचार्यों से ली गई।

अभी तक नहीं हुए सत्यापन

जिले के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा 9वीं और 11वीं के छात्रों की जो सूची विमर्श पोर्टल पर लोड की गई है, उसके सत्यापन के लिए यह सूची विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेजी गई है। लेकिन अभी तक इस सूची का सत्यापन नहीं हो सका है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में आयुक्त द्वारा शीघ्र ही सत्यापित सूची मांगी गई है।

बनाए गए हैं 9 परीक्षा केन्द्र

जिले के एक्सीलेंस स्कूल एवं सभी मॉडल स्कूलों में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए 21 मार्च को परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसके लिए 9 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। विकासखंड स्तर पर एक्सीलेंस स्कूलों एवं जिला स्तरीय एक्सीलेंस स्कूल में प्रवेश परीक्षा होगी। मॉडल स्कूल एवं एक्सीलेंस की 580 सीटों पर छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश दिया जाएगा।

Badri Gautam

होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम करने संबंधी अशासकीय संकल्प पारित

भोपाल, (विसं)। राज्य विधानसभा में शुक्रवार को नर्मदा नदी के तट पर बसे होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम जिला करने संबंधी अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित कर इसे केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।

भाजपा के वरिष्ठ विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा और अन्य सदस्यों की ओर से पेश किए गए अशासकीय संकल्प पर चर्चा में शामिल होते हुए सदस्यों ने कहा कि नर्मदापुरम नाम रखना उचित है। ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखने का आधार स्थानीय जनता की धार्मिक भावनाओं को बताया गया। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है और इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हाल ही में घोषणा की थी कि होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम जिला किया जाएगा।

Badri Gautam

21वीं सदी में शिक्षक शिक्षा का कायाकल्प विषय पर आयोजित दो दिवसीय संगोष्ठी के पहले शिक्षाविदों ने रखे तर्क

शिक्षकों की ट्रेनिंग में बदलाव कर नई शिक्षा नीति को बनाया जाएगा बेहतर

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

शिक्षक बाय चांस नहीं, बाय च्वॉइस बनना चाहिए। ऐसा होने पर वे मन से पढ़ाएंगे और आदर्श विद्यार्थियों का निर्माण करेंगे। आजादी के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई कमीशन बने, नीतियां बनी, परन्तु उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाया।

इस शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए देश भर के शिक्षाविदों ने गंभीर चिंतन किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। इस शिक्षा नीति में शिक्षा की संरचना, पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ शिक्षक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। यह बात शुक्रवार को 21वीं सदी में शिक्षक शिक्षा का कायाकल्प विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा ने कही। दो दिन तक चलने वाली इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में 250 से अधिक शिक्षाविद सहभागिता कर रहे हैं। संगोष्ठी का समापन 6 मार्च को होगा।

देशभर से 250 से अधिक शिक्षाविद कर रहे हैं सहभागिता, 6 मार्च को होगा संगोष्ठी का समापन

Badri Gautam

शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों ने कहा

अच्छा बदलाव आएगा

इस कार्यक्रम के जरिए एक अच्छा बदलाव आएगा। मेरे हिसाब से एक टीचर अगर सच्चा शिक्षक बन जाए तो किसी भी अन्य प्रयास की जरुरत ही नहीं है। एक टीचर को पता होना चाहिए उनका दायित्व क्या है। शिक्षा नीति को यदि कोई बदल सकता है कोई बेहतर कर सकता है तो वो एक शिक्षक ही है।

दिव्यांशु दुबे
भूतपूर्व महानिदेशक एवं कुलपति
चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी, गुजरात

सबको भागीदारी देनी होगी

अभी तक जो शिक्षा नीति थी, उसका इंप्लीमेंटेशन सही से नही हुआ था। नीति तो ठीक थी, लेकिन अब नई शिक्षा नीति और भी बेहतर है। शिक्षा का स्तर अब और भी बढ़ गया है ऐसे में सबको इसमें अपनी भागीदारी देनी होगी, जिससे शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में, इसका अच्छा असर पड़े।

रामकृष्ण राव
अखिल भारतीय अध्यक्ष
विद्या भारती

पूरा ध्यान शिक्षक शिक्षा पर

इस संगोष्ठी का मेन फोकस टीचर्स एजुकेशन पर है। शिक्षकों की ट्रेनिंग में कुछ बदलाव की जरुरत है। यदि हम शिक्षक की ट्रेनिंग नई शिक्षा नीति की तरह से नही करेंगे तो पॉलिसी बस पॉलिसी ही बन कर रह जाएगी। यह दो दिवसीय संगोष्ठी इन्ही मुद्दों पर हो रही है कि पहले हमको शिक्षक को तैयार करना है तब हम आगे बढ़ पाएंगे।

डॉ.सुनील गुप्ता
कुलपति, आरजीपीवी

सीखने की चार स्थितियां पठन, मनन, चिंतन और संकेतन : प्रो. जगदीश कुमार

शुभारंभ समारोह में ऑनलाइन जुड़े जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एम. जगदीश कुमार ने आधुनिक विज्ञान के उदाहरणों को स्पष्ट करते हुए कहा कि लर्निंग बाय डूइंग सीखने का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन आज हमारी शिक्षा सिर्फ लेक्चर सुनने पर केंद्रित है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सीखने की चार स्थितियां बताई हैं. पठन, मनन, चिंतन और संकेतन। आज आधुनिक विज्ञान इसी प्रक्रिया में सीखने को सबसे अधिक प्रभावी मानता है। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई तरीके के प्रयोग शामिल किए गए हैं।

मंथन से उपजा विचार रूपी अमृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सार्थक होगा : मंत्री परमार

स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार ने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आजादी के बाद शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए जो काम होना चाहिए थे, वे नहीं हो पाए। इस राष्ट्रीय में मंथन से उपजा विचार रूपी अमृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मील का पत्थर साबित होगा। संगोष्ठी के दौरान प्राप्त सिफारिशों को मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

शिक्षा सुधार के लिए टास्क फोर्स करेगी काम, दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

कोई संस्थान मर्जी से कुछ भी नहीं पढ़ा सकता हमे इंसान बनाना है आतंकवादी नहीं: शिवराज

शहर प्रतिनिधि, भोपाल । मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा की दिशा और गति तय करने के लिए देश भर के शिक्षाविद् भोपाल में एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम शुभारंभ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई शिक्षण संस्थान अपनी मर्जी से अब कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। हमे एक मर्यादा तय कर दिशा-निर्देश तैयार करने होंगे। शिक्षण संस्थान में बेहतर इंसान बनाना है, आतंकवादी तैयार कराना नहीं। जो शिक्षण संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे है, उन्हें भरपूर सहयोग देना है। शिक्षा में सुधार के लिए गठित हो चुकी टास्क फोर्स प्रभावी ढंग से काम करेगी। छात्रों को सिर्फ लिखा हुआ नहीं पढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कमलनाथ पर हमला करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने बंटाधार कर दिया। मप्र की शिक्षा को कचरा कर दिया था। बड़ी मुश्किल से इसे यहां तक ला पाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना है, जो मुक्ति दिलाए वहीं शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि शिक्षा वह जो इंसान बना दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि संगोष्ठी के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, उसे शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जाएगा। प्रशासन अकादमी में आयोजित संगोष्ठी में प्रदेश के शिक्षकों को छात्रों के बीच तालमेल बैठाने और पढ़ाई कराने के तरीकों के बारे में बताया जाएगा। संगोष्ठी में राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा इंदर सिंह परमार ने शिक्षा की कार्ययोजना को लेकर अपनी बात कही। संगोष्ठी में पहले दिन शिक्षक छात्रों के अधिकार और विशेष शिक्षा के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही शिक्षा में किए प्रयोग के बारे में भी शिक्षा के जानकारों ने शिक्षकों को बताया गया। कार्यक्रम में नई दिल्ली, हैदराबाद, मेरठ, तमिलनाडु, भुवनेश्वर, बिहार और बिलासपुर समेत अन्य जगहों से कुलपति, प्रोफेसर और शिक्षाविद् शामिल हुए। संगोष्ठी का शनिवार शाम चार बजे समापन होगा।

बंद नहीं करेंगे स्कूल, बड़े स्कूल बनेंगे: मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना पीड़ित होने पर आत्मनिर्भर के बारे में काफी चिंतन किया। स्कूल के नाम पर कुछ भी खोल देने से नहीं चलेंगे। हम कोई भी स्कूल बंद नहीं करेंगे, बल्कि नए बड़े स्कूल बनेंगे। बेहतर दिशा देने भर से हमारे यही शिक्षक अच्छा कर सकते है। नई शिक्षा नीति मील का पत्थर साबित होंगी।

प्रशासन अकादमी में राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते सीएम शिवराज सिंह चौहान।

Badri Gautam

पेड़ लगाने स्कूल शिक्षा मंत्री ने खुद गड्ढा खोदा

कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पौधा तोहफे में दिया। कार्यक्रम के बाद खुद परमार ने प्रशासन अकादमी में गैंती फावड़ा चलाकर एक गड्ढा खोदकर यह पौधा लगा दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे भी पौधों की तरह होते हैं। हमें उन्हें अपनी मेहनत से सींचना होता है। हम उन्हें दूसरे के हाथ में नहीं दे सकते, इसलिए स्कूल से ही बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग प्रयास कर रहा है।

सीबीएसई के अनुसार होगी दसवीं और बारहवीं की परीक्षा का सिलेबस

भोपाल (शप्र)। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की तीस अप्रैल से शुरू होने वाली दसवीं-बारहवीं परीक्षा का सिलेबस सीबीएसई के अनुसार होगा। दरअसल मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पूर्व में कोरोना काल को देखते हुए दसवीं-बारहवीं के सिलेबस में कटौती की थी। इसके बाद नया ब्लू प्रिंट जारी किया गया। जिसे शासन ने धारा 9(4)(5) के तहत निरस्त कर दिया था। साथ ही गत दिवस मंडल ने 10वीं-12वीं का नया ब्लू प्रिंट जारी किया है। यह ब्लू प्रिंट सीबीएसई के अनुसार जारी किया गया है। सीबीएसई ने सिलेबस में तीस फीसदी की कटौती की है। मंडल ने भी तीस फीसदी कटौती कर सिलेबस को जारी किया है। इसी सिलेबस के आधार पर अब तीस अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षा होगी।

सिविल जज पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी का आरोप

भोपाल। कटनी में सिविल जज के जाति प्रमाण पत्र के फर्जी होने का मामला राज्य विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से सामने आया है। मंत्री का कहना है कि इस मामले की जांच चल रही है। कांग्रेस विधायक बृजेन्द्र सिंह राठौर ने एक प्रश्न के माध्यम से जानना चाहा है कि क्या झाबुआ में सीजेएम रहे और वर्तमान में कटनी में एडीजे राधेश्याम मडिया द्वारा कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति कोटे का उम्मीदवार बन कर सिविल जज की नौकरी प्राप्त की है। उन्होंने यह भी पूछा है कि राधेश्याम मडिया के विरूद्ध तमाम गंभीर शिकायतें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर प्रेषित करने पर मडिया द्वारा 13 अगस्त 2020 को जिला जज कटनी के माध्यम से स्वैच्छिक त्यागपत्र प्रस्तुत किया है, उनका त्यागपत्र स्वीकारा जा रहा है अथवा मडिया के विरूद्ध आरोपों के संबंध में कोई कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या यह भी सत्य है कि मडिया ने अपनी जन्मतिथि 10 फरवरी 1960 को बदलकर 10 फरवरी 1966 कर ली गई है। जिससे उनको दस फरवरी 2020 को सेवानिवृत हो जाना था जो नहीं किया गया। गृह एवं विधि विधायी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने जबाव में कहा है कि जाति प्रमाण पत्र संबंधी रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। उन्होंने बताया कि मडिया विरूद्ध गंभीर शिकायतें प्राप्त होने के उपरांत 13 अगस्त 2020 को एडीजे की नौकरी से स्वैच्छिक त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया जो उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है अपितु उन्हें निलंबित कर उनके खिलाफ आरोपों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है। जिसमें कार्यवाही लंबित है।

जन्मतिथि में भी हेरफेर, विधानसभा में आया मामला

Badri Gautam

युवक कांग्रेस ने बाल आयोग से की शिकायत

स्कूलों में लेट फीस के नाम पर अवैध वसूली का लगाया आरोप

स्टार समाचार | भोपाल

मध्यप्रदेश में स्कूल खुलने के बाद फीस वसूले जाने की शिकायतें आ रही हैं। अब इसी को मुद्दा बनाते हुए युवक कांग्रेस मैदान में उतर आया है। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को इस संबंध में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि स्कूलों की मनमानी और अवैध वसूली पर अंकुश लगनी चाहिए। अभिभावकों से लेट फीस के नाम पर जबरन वसूली की जा रही है।

इधर, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कहा कि इस तरह की शिकायत मिलते ही संबंधित स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी। युवक कांग्रेस मध्यप्रदेश मीडिया के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने कहा कि फीस वसूली समेत अन्य मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो से शिकायत दर्ज कराई। उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। इसमें जबरन वसूली की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हमने उन्हें बताया कि प्रदेश के ऐसे स्कूलों पर नकेल कसना है।

सरकार और कोर्ट के आदेश के बाद भी स्कूल लेट फीस के नाम पर मनमानी कर रहे हैं। इससे अभिभावक पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। स्कूलों द्वारा लगातार छात्र-छात्राओं पर फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कानूनगो ने छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से मिलकर आश्वासन दिया है कि अगर कोई भी विद्यालय किसी भी छात्र-छात्राओं को परीक्षा देने से या फीस का दबाव बनाता है, तो उस स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी।

Badri Gautam

मध्यप्रदेश में फिर व्यापमं

एक ही कॉलेज से 10 टॉपर, परीक्षा में सभी के अंक और गलतियां भी समान

ग्वालियर। मध्यप्रदेश का व्यापमं एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। 2013 का यह मामला देशभर में चर्चित रहा था। लेकिन राज्य में अब एक बार दूसरे व्यापमं घोटाले को लेकर संदेह जताया जा रहा है। दरअसल, मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं आयोजित कराने वाला मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल जिसे व्यापमं के तौर पर जाना जाता है, एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इसका कारण है कि व्यापमं की ओर से आयोजित की गई कृषि विस्तार और कृषि विकास अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में एक अनोखा संयोग देखने को मिला है। कई लोग इसे दूसरा व्यापमं घोटाला भी बता रहे हैं। इसे संयोग कहा जाए या धांधली कि राज्य भर्ती परीक्षा में एक ही कॉलेज के 10 छात्र टॉप करते हैं। वे सभी शीर्ष 10 में जगह पाते हैं। इन सभी 10 छात्रों के प्राप्तांक भी एक समान है। इतना ही नहीं इन छात्रों की ओर से परीक्षा में की गई गलतियां, त्रुटियां और उनकी जाति भी एक समान है। मामला सामने के बाद एक मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल से लेकर मध्यप्रदेश सरकार तक हर कोई हैरान -परेशान हैं। दूसरे अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग है कि जांच से पहले इस परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए। दूसरे व्यापमं घोटाले की आशंका के बीच मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं।

Badri Gautam

फरवरी में हुई थी परीक्षा

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापमं की ओर से 10-11 फरवरी को कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी पद के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। 17 फरवरी को इस परीक्षा की आंसर शीट के साथ सफल उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट भी जारी की गई। जब परिणाम आया तो पता चला कि वरीयता सूची में शीर्ष 10 स्थान हासिल करने वाले सभी अभ्यर्थी एक ही कॉलेज से हैं।

ग्वालियर के कॉलेज से हैं टॉप 10 छात्र

इन शीर्ष 10 उम्मीदवारों ने राजकीय कृषि कॉलेज, ग्वालियर से बीएससी की पढ़ाई की है। इन्हें परीक्षा में एक जैसे प्राप्तांक मिले हैं और सभी ने परीक्षा में गलतियां भी एक जैसी ही की हैं। इन समानताओं के कारण व्यापमं की भर्ती परीक्षा में धांधली का शक गहरा गया है। इतना ही नहीं इनमें से नौ उम्मीदवार एक ही जाति के हैं। इसे लेकर परीक्षा में शामिल हुए अन्य उम्मीदवारों ने घोटाले का आरोप लगाया है।

सामान्य ज्ञान की परीक्षा में मिले समान अंक

हैरान करने योग्य बात ये है कि सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज की परीक्षा में इन सभी 10 उम्मीदवारों को एक जैसे अंक मिले हैं। गौर करने योग्य यह भी है कि इन टॉपर्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड भी टॉपर जैसा नहीं है। जानकारी के अनुसार, एक टॉपर उम्मीदवार को गणित में पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं, जबकि बीएससी की परीक्षा के दौरान वह सांख्यिकी विषय में चार बार फेल हो चुका है। उसने डिग्री आठ साल में पूरी की थी। चौंकाने वाले बात यह भी है कि इन सभी ने जिन सवालों के गलत उत्तर दिए हैं, वे भी एक जैसे हैं। फिर भी ये टॉपर हैं।

ब्लैकलिस्टेड कंपनी एनएसईआईटी ने कराई थी परीक्षा

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापमं की ओर से इस परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी एनएसईआईटी कंपनी को दी थी। यह कंपनी पहले भी धांधली के आरोपों से घिरी रही है। 2017 में उत्तर प्रदेश की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के चलते एनएसईआईटी को ब्लैकलिस्ट किया गया था। इस बार टॉप 10 में शामिल उम्मीदवारों को 200 में 195 और 194 अंक मिले हैं, इस परीक्षा के इतिहास में इतने नंबर किसी को नहीं मिले। खैर, मुख्यमंत्री शिवराज ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं।

वयस्क होने तक नहीं, स्नातक की उपाधि मिलने तक बेटे का खर्च उठाए पिता

नई दिल्ली स्वससे।

शीर्ष न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा कि पिता को बेटे का खर्च सिर्फ 18 साल की उम्र यानी व्यस्क होने तक नहीं बल्कि उसके पहली डिग्री पाने तक उठाना होगा। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि स्नातक को अब बेसिक शिक्षा माना जाता है। न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने एक व्यक्ति को निर्देश दिया कि वह 31 मार्च 2027 तक अपने बेटे की शिक्षा का खर्च उठाए। न्यायालय ने कहा कि बच्चे को अपना स्नातक पूरा करने तक आर्थिक सहयोग की जरूरत है। कुटुम्ब न्यायालय के आदेश में थोड़ा बदलाव करते हुए न्यायालय ने व्यक्ति को कहा, आज के जमाने में जब कॉलेज पूरा कर लेने पर बेसिक डिग्री मिलती है ऐसे में बेटे को सिर्फ बालिग होने यानी 18 साल की उम्र तक पैसे देना काफी नहीं है। आपको उसकी पढ़ाई का खर्च कम से कम तब तक उठाना चाहिए जब तक वह कॉलेज की डिग्री नहीं ले लेता। यह व्यक्ति कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है। साल 2005 में पत्नी से तलाक के बाद कर्नाटक की कुटुम्ब ने उन्हें हर महीने अपने बेटे के लिए 20 हजार रुपए खर्चा देने का आदेश दिया था।

Badri Gautam

बायोडायवर्सिटी पार्क में हुए घोटाले की जांच शुरू

35 लाख के एक और घोटाले में फंसी गर्दन

आर्थिक अपराध शाखा की कालेज में दबिश

स्टार समाचार | सतना

स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना में जैव विविधता पार्क निर्माण के भुगतान में की गई गड़बड़ी के बाद राज्य आर्थिक अपराध शाखा के अतिरिक्त संचालक विनोद श्रीवास्तव, प्राचार्य सतेन्द्र शर्मा और स्नातकोत्तर कॉलेज सतना के प्राध्यापकों समेत 13 लोगों के विरुद्ध हुई एफआईआर की विवेचना शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को मोहित सक्सेना के नेतृत्व में छह सदस्यीय टीम सतना कॉलेज पहुंचकर दस्तावेजों की पड़ताल में जुट गई है। गौरतलब है कि आर्थिक अपराध शाखा में 13 लोगों के विरुद्ध शिकायत के बाद की गई शुक्रवार को एफआईआर की विवेचना करने टीम जुट गई है। सुबह साढ़े 10 बजे से स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना में दस्तावेजों की पड़ताल निरीक्षक मोहित सक्सेना के नेतृत्व में की जा रही है। सुबह से शुरू हुई यह कार्रवाई देर रात तक चलती रही। बताया गया है कि जैव विविधता पार्क में की गई गड़बड़ी के अहम दस्तावेजों को जब्त भी किया गया था। बताया गया है कि अभी और बहुत से दस्तावेज जो नहीं मिल रहे हैं, उनकी तलाश जारी है।

Badri Gautam

क्या था मामला

स्नातकोत्तर कॉलेज सतना में जैव विविधता पार्क निर्माण के भुगतान में की गई गड़बड़ी की शिकायत के बाद आर्थिक अपराध शाखा रीवा में 13 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना में जैव विविधता पार्क निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान शासन द्वारा वर्ष 2013 में स्वीकृत किया गया था। निविदा प्रक्रिया के तहत न्यूनतम निविदाकार फर्म देवलैण्ड स्कैपर सतना की निविदा दर कम होने से उक्त निविदाकार से कार्य कराया गया था। जिसका भुगतान 4 लाख 99 हजार 400 रुपए शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना द्वारा किया गया था। खास बात यह है कि निविदाकार द्वारा अतिरिक्त कार्य के नाम पर अतिरिक्त देयक भुगतान प्रस्तुत किए गए थे। जिसमें महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य डॉ. हर्षवर्धन एवं धीरेन्द्र सिंह ने अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग संभाग रीवा को अवगत कराया था। उन्होंने स्पष्ट बताया भी था कि निविदाकार द्वारा न तो कोई अतिरिक्त कार्य कराया गया है न ही इसका किसी प्रकार का भुगतान ही बकाया है।

इन्हें बनाया गया था आरोपी

ईओडब्ल्यू के आने की खबर लगते ही कई आरोपी भाग खड़े हुए। बताया गया है कि बायोटेक विभाग के राजेश गर्ग कार्यालय से चंपत हो गए। गौरतलब है कि शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना में बनाए गए जैव विविधता पार्क के निर्माण के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार पर स्वशासी महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य एवं डॉ. सतेन्द्र शर्मा, डॉ. विनोद कुमार श्रीवास्तव अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग, राजेश गर्ग बायोटेक विभाग, आरआर गुप्ता, केएल मौर्य प्रध्यापक अर्थशास्त्र, प्रदीप मिश्रा, गोविंद प्रसाद द्विवेदी, एनके भगत, एनपी अग्रवाल, सुनील शर्मा, संविदाकार राघवेंद्र शर्मा, अमित कुमार तथा नंदलाल कुशवाहा को आरोपी बनाया गया है।

35 लाख रुपए के दुरुपयोग पर होगी पृथक से जांच

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना के तत्कालीन प्राचार्य सतेन्द्र शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध गोपनीय कार्यों के लिए प्रश्न पत्र की छपाई एवं लगाए गए वाहनों में तकरीबन 35 लाख रुपए के शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है। इन भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों की अलग से जांच की जा रही है। शुक्रवार को सतना स्नातकोत्तर कॉलेज के प्राचार्य एवं प्राध्यापकों के संबंध में की जा रही विवेचना में निरीक्षक मोहित सक्सेना के नेतृत्व में कॉलेज से दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं।

छात्र को श्रमिक बनाकर कर दिया फर्जी भुगतान

शैक्षणिक वर्ष 2009 एवं 2017-18 में महाविद्यालय के छात्र अमित कुमार सिंगोत एवं नंदलाल कुशवाहा को श्रमिक के रूप में मस्टर रोल पर काम दिखाकर पारिश्रमिक के रूप में 2 लाख 71 हजार 631 का फर्जी भुगतान कर दिया गया। इस तरह की गई गड़बड़ी की शिकायत ईओडब्ल्यू मुख्यालय भोपाल में शिकायत क्रमांक 2419 पंजीबद्ध कर सत्यापन के लिए निरीक्षक श्रीमती गरिमा त्रिपाठी द्वारा कराए जाने पर शिकायत के सत्यता की पुष्टि हुई। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना में डॉ. सतेन्द्र शर्मा की पदस्थापना होने के बाद अतिरिक्त कार्य के नाम पर निविदाकार द्वारा प्रस्तुत देयकों के भुगतान के संबंध में एक राय होकर आपराधिक षड़यंत्र रचकर बगैर निविदा आमंत्रण तथा कार्य के मूल्यांकन कराए बगैर ही एडी विनोद श्रीवास्तव उच्च शिक्षा रीवा संभाग द्वारा निविदाकार को 4 लाख 75 हजार 500 के भुगतान की अनुमति दे दी। महाविद्यालय के वित्त समिति पदाधिकारियों तथा बायोडायवर्सिटीज कार्य के प्रभारी डॉ. राजेश गर्ग द्वारा उक्त भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर डॉ. शर्मा द्वारा भुगतान कर दिया गया।

स्कूल में घुसकर चोर बटोर ले गए सामान

शिवपुरी, ब्यूरो। पिछोर के ग्राम बदरखा में स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में बीती रात्रि अज्ञात चोर घुस गए। जो स्कूल में लगे 9 पंखे, 9 एलईडी बल्ब, 150 मीटर केवल, 5 कुर्सी और एक गैस सिलेंडर चोरी कर ले गए। जिसकी जानकारी स्कूल की प्राचार्य वंदना पत्नी महेश प्रताप सिंह चौहान को लगी तो वह थाने पहुंची। जहां उन्होंने अज्ञात चोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने मामले में भादवि की धारा 457 और 380 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर चोर की तलाश शुरू कर दी है।

Badri Gautam

पीईटी 17 जून को, इस बार सभी 11 प्रवेश परीक्षाएं लेगा छग व्यापम

रायपुर । छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा इस वर्ष सभी 11 प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बीते वर्ष कोरोना के कारण व्यापम ने सभी प्रवेश परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। प्रवेश परीक्षाओं के स्थान पर 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। व्यापम की प्रवेश परीक्षाएं प्री इंजीनियरिंग टेस्ट अर्थात पीईटी के साथ 17 जून से प्रारंभ होंगी। इसी दिन प्री फॉर्मेसी टेस्ट भी लिया जाएगा। इन दो प्रवेश परीक्षाओं के अलावा प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट और प्री एमसीए के परिणाम जारी किए गए हैं। व्यापम द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, अन्य विभागों की प्रवेश परीक्षाओं की तारीखें संबंधित विभागों से सहमति प्राप्त होने के बाद ही जारी की जाएंगी। इस वर्ष 12वीं की परीक्षाएं कोरोना के कारण देर से समाप्त हो रही हैं, इसलिए प्रवेश परीक्षाएं भी अपेक्षाकृत देर से हो रही हैं।

Badri Gautam

पाटई गांव में परीक्षा केन्द्र की मांग

घाटीगांव, नि.प्र.। ग्वालियर जिले के घाटीगांव विकासखंड के ग्राम पाटई सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल की वार्षिक बोर्ड परीक्षा के लिए पाटई गांव में परीक्षा केन्द्र स्थापित करने की मांग की है। एक प्रेस विज्ञप्ति में ग्राम पंचायत पाटई के सरपंच दिलीप सिंह रावत ने बताया कि पाटई सहित करीब बीस गांवों के छात्र-छात्राओं को परीक्षा देने के लिए गांव से काफी दूर जाना पड़ता है। परिवहन सुविधा के अभाव में कई छात्र-छात्राएं जहां परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो वहीं कई छात्र-छात्राएं परीक्षा से वंचित भी रह जाते हैं, इसलिए छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखकर पाटई गांव में परीक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए। श्री रावत ने ग्राम पुलिया के पुरा में उप आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत पाटई में शांतिधाम से अटाई वाला रोड, पाटई से समराई रोड निर्माण की मांग भी शासन व प्रशासन से की है।

Badri Gautam

राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बने भदौरिया

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के नये अध्यक्ष सुरेंद सिंह भदौरिया बनाये गए हैं। संघ ने यह निर्णय 17वीं त्रिवार्षिक प्रदेश अधिवेशन में लिया। इस दौरान अधिवशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मागों का निराकरण सरकार द्वारा नहीं होने के कारण सुझाव भी लिये गए हैं। 7 फरवरी को हुई इस बैठक में प्रदेश भर से पहुंचे सदस्यों द्वारा पदाधिकारियों का निर्वाचन किया। जिसमें प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र शर्मा और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी केवी मेवारे को सौंपी गई है। प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी चौबे ने बताया कि संघ द्वारा कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है। जिसमें कारोना काल में रोकी गई वेतनवृद्धि एवं महगाई भत्ते का तत्काल भुगतान करवाने के आदेश जारी करने की मांग प्रमुख है। इसके साथ ही विभागों में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत एवं अन्य कार्यपालिक कर्मचारियों को निकाले जाने की प्रथा को समाप्त कर सभी के संविलियन के कार्यवाही की मांग की जाएगी। इसमें प्रत्येक अधिकारियों/ कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान देतनमान दिया जावे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशानुसार पदोन्नति के आदेश जारी किये जायें, अनुकपा नियुक्ति में लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाये, संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की जावे, स्वास्थ्य कर्मचारियों को ब्रम्हस्वरूप समिति का लाभ दिया जावे और पुरानी पेंशन बहाल की जाय जैसी मांग भी इसमें शामिल है।

Badri Gautam

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षक-शिक्षा विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में कहा

शिक्षा का अर्थ तोते की तरह रटना, बस्ते के बोझ से दबे रहना और परीक्षा देना नहीं है

शिक्षा से बच्चों का स्वाभाविक विकास तथा उनकी प्रतिभाओं का प्रकटीकरण होना चाहिए

भास्कर ब्यूरो, भोपाल।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना होना चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा शिक्षक-शिक्षा का कायाकल्प पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा, दत्तात्रेय होसबले और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने शिक्षा पथ प्रदीपिका पुस्तक का विमोचन भी किया।इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शिक्षा का अर्थ तोते की तरह रटना, बस्ते के बोझ से दबे रहना तथा परीक्षा देना नहीं है। शिक्षा से बच्चों का स्वाभाविक विकास तथा उनकी प्रतिभाओं का प्रकटीकरण होना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों के शिक्षण-प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में इन तीनों बातों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। इन्हें मध्यप्रदेश में लागू किया जाएगा। कक्षा छठवीं से व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी।वहीं उन्होंने कहा कि चौहान ने कहा कि शिक्षा देना केवल सरकार का कार्य नहीं है। समाज के सहयोग से शिक्षा दी जानी चाहिए। इस क्षेत्र में विद्या भारती जैसी संस्थाए काफी अच्छा कार्य कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चौहान ने अपने गांव जैत के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रतन चंद जैन को याद करते हुए कहा कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा मेरे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थियों को रामचरित मानस पढ़ाया करते थे।

मास्क पहनने पर ही स्कूल में मिलेगा प्रवेश

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्कूल खोले जाने की तैयारी से पहले सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर अगर है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए है कि बच्चों को मास्क पहनाकर ही प्रवेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने जन्म दिवस पर मंत्रालय में पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। परीक्षा आयोजन को लेकर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा।

जो चाहे पढ़ाए, यह नहीं चलेगा

सीएम ने स्पष्ट से कहा कि शिक्षण संस्थाएं अमर्यादित शिक्षा देकर विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करें, यह नहीं चलेगा। यदि कोई संस्थान गलत शिक्षा देता है, तो उसे रोका जाएगा। हम आतंकवादी नहीं बनने दे सकते। स्कूलों के नाम पर कुछ भी खोला जाए, यह नहीं चलेगा।

शिक्षाविदों को जोड़ा जाए

मुख्यमंत्री कहा कि मध्यप्रदेश पहला राज्य है जहां नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें प्रदेश के विभिन्न शिक्षाविदों को जोड़ा जाए, जो नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को मध्यप्रदेश में किस तरह व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए, इस संबंध में सुझाव दें।

मंथन से उपजे विचार नीति में होगा अमल : परमार

स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग सतत प्रयास कर रहा है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था भारत केंद्रित, गुणवत्तापूर्ण और ज्ञान आधारित होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान और एनसीटीई के संयुक्त तत्वधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। देशभर के विद्वान, विश्वविद्यालय के कुलपति अलग अलग सत्रों में अपना मार्गदर्शन देंगे। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिक्षक-शिक्षा के ऊपर व्यापक मंथन और चिंतन किया जाएगा। इस मंथन से उपजा विचार रूपी अमृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मील का पत्थर साबित होगा। संगोष्ठी के दौरान प्राप्त सिफारिशों को मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

Badri Gautam

भ्रष्टाचार • रंगेहाथों पकड़ा था, इसीलिए आईएएस अवॉर्ड नहीं हुआ

दस हजार की घूस, शिवपुरी के पूर्व एडीएम शेख को पांच साल की कैद

भास्कर न्यूज | शिवपुरी

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय की कोर्ट ने शुक्रवार को 10 हजार रुपए की रिश्वत के मामले में शिवपुरी जिले में एडीएम रहे जेडयू शेख (वर्तमान में मंत्रालय में पदस्थ) को पांच साल के सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। छह साल पहले लोकायुक्त पुलिस ने जेडयू शेख को घूस लेते हुए रंगे हाथ उनके ही चैंबर में पकड़ा था। रिश्वतकांड में नाम आ जाने की वजह से इन्हें आईएएस अवार्ड भी नहीं हो पाया था, जबकि इस कांड के अगले महीने ही होने वाली डीपीसी में इनका प्रस्तावित था। इसी रिश्वत मामले में कोर्ट ने बाबू (वर्तमान में रिटायर) रामगोपाल राठौर को भी चार साल का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। मालूम हो कि तत्कालीन एडीएम शेख के पास उस समय खनिज अधिकारी का प्रभार था। एक खदान की लीज के बदले में ही रिश्वत मांगी गई थी। फरियादी दिवाकर अग्रवाल ने शिवपुरी कलेक्टोरेट में एक खदान की लीज के लिए आवेदन किया था। इसके लिए खनिज सेक्शन के क्लर्क रामगोपाल राठौर ने 30 हजार रु. की रिश्वत मांगी थी। दिवाकर को बताया था कि एडीएम शेख को भी हिस्सा देना होगा। गोपाल ने दिवाकर की बात भी एडीएम शेख से करा दी थी। दिवाकर ने लोकायुक्त में मामले की शिकायत कर दी। शिकायत सच पाने पर लोकायुक्त टीम ने रिश्वत की पहली किस्त के 15 हजार रुपए केमिकल युक्त नोट दिवाकर के जरिए एडीएम शेख को भेजे। इसमें दस हजार रुपए एडीएम और 5 हजार रुपए बाबू का हिस्सा था। 7 नवंबर 2015 को एडीएम शेख ने जैसे ही रकम हाथ में ली तो इशारा पाकर लोकायुक्त टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद क्लर्क गोपाल को भी हिरासत में ले लिया था।

Badri Gautam

कोरोना योद्धाओं को मिले प्रोत्साहन राशि

प्रतिनिधि, जबलपुर| बहुउद्देश्यी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ब्रम्हस्वरूप वेतनमान में लाभ की जगह उनका शोषण ही अधिक किया जा रहा है। आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर में गलत निर्धारण से लाखों रुपए की रिकवरी आ रही है और अभी तक उन्हें प्रोत्साहन राशि भी शासन द्वारा नहीं दी जा रही है। ऐसे आरोप मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अर्वेन्द्र राजपूत, आलोक अग्निहोत्री, मुकेश सिंह, मुन्ना लाल पटैल, वीरेन्द्र तिवारी एवं ब्रजेश मिश्रा ने लगाते हुए उचित कार्रवाई की माँग की है।

सहकारिता कर्मियों को भी लगे वैक्सीन-जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश यादव एवं राहुल तिवारी जिला अध्यक्ष सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री व सहकारिता मंत्री से सहकारिता कर्मचारियों के लिए भी निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाने की माँग की है।

Badri Gautam

अजाक्स सौंपेगा ज्ञापन- म.प्र.अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष योगेश चौधरी का कहना है कि प्रत्येक हरिजन थाना में पुलिस निरीक्षक एससी-एसटी का होने और पदोन्नति लागू करने की माँगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। संघ के अजय सोनकर, राजेन्द्र तेकाम, राकेश समुन्द्रे, दिनेश बागरी एवं किशोर दाहिया मौजूद थे।

सीमांकन न होने से रुके हैं निर्माण कार्य-म.प्र.शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वदीप पटैरिया, प्रदीप पटैल, विजय शंकर बाजपेयी, का आरोप है कि शिक्षा विभाग की उदासीनता से नगर के सभी स्कूलों का सीमांकन एवं नामांकन नहीं हो पा रहा है और इसलिए नवीन भवन, अतिरिक्त कक्ष एवं बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण तक नहीं हो रहा है।

पेंशनर्स को राहत नहीं- राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में पेंशनर्स एवं कर्मचारियों को कोई राहत नहीं देने से उनमें निराशा बनी हुई है। ऐसे आरोप पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष श्याम जोशी, वरिष्ठ उप प्रांताध्यक्ष गणेश दत्त जोशी, प्रांतीय महामंत्री एचपी उरमलिया एवं एलएन कैसासिया ने लगाए हैं।